कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

केरल की विभिन्न पंचायतों में भाजपा की जीत.................................... 6
प्रमिला शशिधरन बर्नी पलक्कड नगरपालिका की चेयरपर्सन.................... 7
सर्बानंद सोनोवाल असम भाजपा अध्यक्ष नियुक्त................................. 8

सरकार की उपलब्धियां

15 प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई और भी आसान.................................... 9
जन धन खाता योजना में 19 करोड़ नए खाते खुले.............................. 11

वैचारिकी

अब्दुल्ला द्वारा जुलाई समझौते का उल्लंघन स्वतंत्र कश्मीर की रूपरेखा तैयार
पं. दीनदयाल उपाध्याय.. 12

श्रद्धांजलि

अशोक सिंहल नहीं रहे.. 14

लेख

यह रास्ता कांग्रेस को कहां ले जाएगा
– **बलबीर पुंज**.. 26
संविधान दिवस की सार्थकता
– **कृपाशंकर चौबे**... 27

अन्य

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा.. 16
जी–20 शिखर सम्मेलन.. 23
रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मेलन 2015.................................... 29

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को गुरुनानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

सोशल मीडिया से...

फेसबुक

जगत प्रकाश नड्डा

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के मामलों के बाद, हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार किसी और के चलते नहीं बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री के कारण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

मुख्तार अब्बास नकवी

भावनगर, गुजरात में अल्पसंख्यक समाज के सम्मेलन में हिस्सा लिया। मोदी सरकार का संकल्प विकास की रोशनी को आखिरी जरूरतमंद तक पहुंचाना है। सौहार्द और एकता की ताकत से अलगाव और बिखराव की साजिशों को परास्त किया जा सकता है।

राजीव प्रताप रूडी

राजस्थान के विभिन्न पहलों का स्वागत करते हुए वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए शुरू किए गए प्रमुख सुधार प्रशंसनीय है।

twitter

श्री राजनाथ सिंह *@BJPRajnathSingh*

हमें नेहरूजी की नीतियों से मतभेद हैं, लेकिन हम जन-कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने के उनके इरादे पर शक नहीं कर सकते। पंडित नेहरू दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने समझा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित एक सरकार समय की जरूरत थी। नेहरूजी जैसे नेताओं को धन्यवाद कि भारत में आज वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र, एक संप्रभु संसद और स्वतंत्र प्रेस है।

रविशंकर प्रसाद *@rsprasad*

इमरान खान अलवर में संस्कृत स्कूल में गणित सिखाते हैं। उन्होंने चार विभिन्न विषयों के लिए मोबाइल एप्स बनाए, जिसे 30 लाख से अधिक छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने फोन पर इमरान खान से बात की और उनकी उपलब्धि एवं समाज के लिए उनके योगदान हेतु उन्हें बधाई दी।

पाथेय

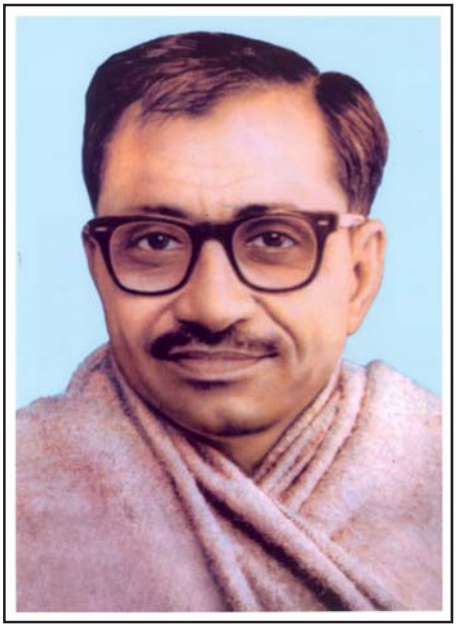

धर्म क्या है?

रिलीजन यानी मत, पंथ, मजहब है, 'धर्म' नहीं। धर्म तो एक व्यापक चीज है। यह जीवन के सभी पहलुओं से संबंध रखनेवाली चीज है। उससे समाज की धारणा होती है। उससे सृष्टि की धारणा होती है। यह धारणा करनेवाली जो चीज है, 'धर्म' है।

धर्म के मूलभूत तत्त्व सनातन और सर्वव्यापी हैं। हां, उनका व्यवहार देश, काल और परिस्थिति सापेक्ष होता है।

इन नियमों की संपूर्ण संहिता और उसके तात्त्विक आधार का नाम 'धर्म' है। ये नियम मनमाने नहीं हो सकते। उनसे उस सत्ता की धारणा होनी चाहिए जिसके लिए वे बने हैं तथा वे दूसरी सत्ता के अविरोधी तथा पोषक होने चाहिए।

– पं. दीनदयाल उपाध्याय

आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो पूरा विश्व

लंदन के वेम्बले स्टेडियम में ब्रिटिश भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत विश्व को दो बड़ी समस्याएं आतंकवाद एवं जलवायु परिवर्तन के बीच राह दिखा सकता है। ठीक इसके दूसरे दिन पेरिस में हुए आतंकवादी हमले जिसमें 130 लोग मारे गये तथा 368 घायल हुए, से पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। वैश्विक आतंकवाद के उभरने के बाद यह अब तक के सबसे भयानक हमलों में से एक है। नरेन्द्र मोदी विश्व के लगभग हर मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को उठाते तथा पूरे विश्व को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होने की अपील करते रहे हैं। अनेक अवसरों पर उन्होंने ठीक ही कहा है कि यह एक वैश्विक युद्ध है और सभी देशों के एकजुट हुए बिना आतंकवाद को मात देना कठिन होगा। यह कुछ एक देशों के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे मानवता के विरुद्ध है इसलिए यह अब समय की मांग है कि पूरा विश्व दृढ़ता से आतंकवाद को हर स्तर पर पराजित करने का संकल्प ले।

भारत आतंकवाद का सबसे अधिक शिकार रहा है। भारत उन दिनों से आतंकवाद से दो-दो हाथ कर रहा है जब पूरा विश्व इसके खतरों से अनजान था। दशकों से हो रहे आतंकवादी हमलों में हजारों निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं। भारत के इन अनुभवों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मुद्दे को विश्व पटल पर प्रमुखता से उठा रहे हैं तथा आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक एवं साझा वैश्विक रणनीति के लिए जनमत निर्माण कर रहे हैं। 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद विश्व ने भी इस मसले को गंभीरता से लेना शुरु किया है।

अब पेरिस हमले और 26/11 मुंबई हमले में भी कई समानताएं देखी जा रही हैं। भारत के संदर्भ में पाकिस्तान को आतंकवाद के पीछे माना जाता है और कई आतंकी हमलों की जड़ें पाकिस्तान में पाई गई हैं। अनेक हमलों के षड्यंत्र पाकिस्तान में रचे गये और पाकिस्तान द्वारा भेजे गये आतंकियों द्वारा अंजाम दिये गये। पाकिस्तान में आतंकियों के प्रशिक्षण शिविरों के भी प्रमाण मिले हैं परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान इन पर कार्रवाई करना तो दूर इन प्रमाणों को नकारने में ही लगा रहा है। इतना ही नहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने एवं समर्थन करने वालों को पाकिस्तान पनाह देता रहा है। इस रवैये पर ध्यान देकर उस पर अंकुश लगाना चाहिए और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध को कमजोर करने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।

यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री आतंकवाद के विरुद्ध बोल रहे हैं और पूरे विश्व से एकजुटता की अपील कर रहे हैं तो कुछ कांग्रेसी नेता पाकिस्तान की प्रशंसा कर पाकिस्तानी धरती पर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। पूरे देश ने इसकी एक स्वर में आलोचना की है परंतु कांग्रेस ने अब तक इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। सलमान खुर्शीद एवं मणिशंकर अय्यर न केवल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं बल्कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री भी हैं और उनके गैर-जिम्मेदाराना बयानों से कांग्रेस की गिरती छवि में और बट्टा लगा है। कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों पर सस्ती राजनीति उसे भारी पड़ेगी। कांग्रेस इन नेताओं पर कार्रवाई न कर अपने लिए ही कांटा बो रही है।

विश्व के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंक के विरुद्ध वैश्विक रणनीति को अपील को गंभीरता से लेना चाहिए। वे पहले दिन से ही आतंकवाद पर पूरे विश्व को आगाह कर रहे हैं और अधिकतर देशों के साथ इस मुद्दे पर कई प्रभावी समझौते भी करने में सफल रहे हैं। अब यह समय की मांग है कि पूरा विश्व आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो इस खतरे को हमेशा के लिए धरती से उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। ■

केरल की विभिन्न पंचायतों में भाजपा की जीत

भाजपा ने तिरूवनंतपुरम में 19 नवम्बर 2015 को हुए दो ग्राम पंचायतों में पहली बार विजय प्राप्त की है। भाजपा विलाबूरकल और मारानल्लोर पंचायतों में भी विजयी हुई है।

इसी प्रकार, भाजपा ने कल्लीयूर ग्राम पंचायतों के कुल 20 वार्डों में से 10 सीटों पर कब्जा कर लिया है। एलडीएफ और यूडीएफ को क्रमश: पांच और चार सीटों पर विजय हासिल हो पाई है। अकेले स्वतंत्र प्रत्याशी ने भी भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। आर. जयालक्ष्मी को कल्लीपूर पंचायत का अध्यक्ष चुना गया है।

वेंगनूर पंचायत में भाजपा को स्पष्ट बहुमत होने पर जीएस श्रीकला को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भाजपा ने पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दो ब्लॉक पंचायत सीटों और एक जिला पंचायत सीट पर भी कब्जा जमा लिया है।

तिरूवन्दूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी भाजपा के प्रत्याशियों ने निर्वाचित होकर जिले में परचम फहरा दिया है। यह पहली बार है कि पार्टी ने जिले की पंचायत में अपने ही बल पर सत्ता प्राप्त करने में सफल हुई है। पार्टी के पास 13 सदस्यीय पंचायत में छह सदस्य थे। यूडीएफ और एलडीएफ के पास क्रमश: पांच और दो सदस्य थे। चुनाव में एलडीएफ सदस्य चुनाव से बाहर रहे।

भाजपा अध्यक्षीय प्रत्याशी जलज रविन्द्रन को इस चुनाव में छह वोट मिले जबकि यूडीएफ को पांच वोट प्राप्त हुए। भाजपा के मोहनन वलिया नीतिल उपाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त हुई जिसमें उसके यूडीएफ का एक वोट के अंतर से हरा दिया।

जब पंचायत के भविष्य के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि पार्टी के पास स्थानीय निकाय में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो फिर भी इसका समाधान निकलेगा। इस पर श्री वल्लीमकुलम परमेश्वरन, भाजपा जिला अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि इसके जरा भी आशंका नहीं है कि अगले पांच वर्षों तक पार्टी सत्ता में बनी रहेगी।

जब यह पूछा गया कि क्या भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एलडीएफ और यूडीएफ आपस में मिल नहीं जाएंगे तो कहा गया कि इस प्रकार की स्थिति

तिरूवन्दूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी भाजपा के प्रत्याशियों ने निर्वाचित होकर जिले में परचम फहरा दिया है। यह पहली बार है कि पार्टी ने जिले की पंचायत में अपने ही बल पर सत्ता प्राप्त करने में सफल हुई है। पार्टी के पास 13 सदस्यीय पंचायत में छह सदस्य थे। यूडीएफ और एलडीएफ के पास क्रमश: पांच और दो सदस्य थे। चुनाव में एलडीएफ सदस्य चुनाव से बाहर रहे।

बनने की कोई उम्मीद नहीं है। किन्तु, कहा गया कि यदि ऐसी स्थिति बनती भी है तो भी इन दोनों मोर्चों की वास्तविक राजनीति का पर्दाफाश ही होगा।

भाजपा ने अलपूजा और अन्य जिलों में कई स्थानीय निकायों में भी निर्णायक भूमिका निभाई है। प्रदेश पार्टी इकाई का यह निर्णय था कि पार्टी यूडीएफ या एलडीएफ किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी।

भाजपा ने 2010 के चुनावों के मुकाबले जिले के स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी स्थिति में सुधार किया

है। पार्टी के पार जिले की ग्राम पंचायतों में 120 सदस्य थे जब कि अब 49 सीटें हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 107 सीटों पर विजय हासिल की गई है जब कि पार्टी के समर्थन से 13 निर्दलियों को भी विजय दिलाई गई है।

नगर पालिका चुनावों के मामले में पार्टी को 28 सीटें मिलीं, जिनमें पांच निर्दलीय शामिल हैं। पार्टी को 2010 के चुनावों में जिले की किसी नगरपालिकाओं में कोई सदस्य नहीं था। अब पार्टी के पास अलमूजा नगरपालिका में चार सदस्य हैं।

हरिपद में पार्टी के पास एक सदस्य और एक निर्दलीय हैं। कपनकुलम में सात सदस्य हैं। मवेलिकारा नगर पालिका में नौ सदस्य हैं जिसमें एक निर्दलीय शामिल है। चेंगान्नूर में पार्टी के तीन सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य हैं। भाजपा की सहयोगी पीसी थामस के नेतृत्व वाली केरल कांग्रेस के दो सदस्य भी चेंगान्नूर से विजयी हुए हैं। ■

भाजपा तमिल में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए एक करोड़ रुपए प्रदान करेगी

भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वह तमिलनाडु में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए एक करोड़ रुपए प्रदान करेगी। यह घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने की। यह ध्यान देने योग्य है कि हाल की विगत प्राकृतिक आपदा के कारण बाढ़ ने बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी ने आपदा से प्रभावित सार्वजनिक सम्पत्तियों की हानि का अनुमान लगाने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगा।■

प्रमिला शशिधरन बनीं पलक्कड नगरपालिका की चेयरपर्सन

श्रीमती प्रमिला शशिधरन सन् 2000 में उस समय पार्टियों का विकल्प बनी थी जब पलक्कड नगरपालिका के पुथूर डिवीजन को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया था। सन् 2000 तक श्रीमती प्रमिला शशिधरन, जो अब 51 वर्ष की है, ने कभी भी चुनावी राजनीति में शामिल न होने की योजना बनाई थी। पन्द्रह वर्षों के बाद उन्होंने राजनीति में शामिल होने का फैसला कर एक इतिहास रचा है कि आज वह केरल में नगर म्युनिसिपिल की पहली अध्यक्ष बनकर सामने आई है। अब जबकि पलक्कड म्युनिसिपिल कौसिल का पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है, भाजपा ने श्रीमती शशिधरन को चेयरपर्सन बनाया है। पार्टी पहले ही पलक्कड म्युनिसिपिलिटी में अकेली सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है और इस प्रकार केरल में पहली अर्बन गवर्निंग बॉडी सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने यह भी आगे कहा कि 2000 में महिला आरक्षण के कारण राजनीतिक दलों ने स्थानीय महिला की तलाश थी, अत: श्रीमती शशिधरन को इस पद पर बिठाया गया है। उस समय कांग्रेस, सीपीएम और भाजपा मेरे पास आए थे। हालांकि मेरे माता-पिता पारम्परिक रूप से कांग्रेस के प्रति वफादार थे, फिर भी मैंने अपने पति के कहने पर भाजपा में शामिल हुई।

2005 के अगले सिविक चुनावों में मैंने जनरल सीट का विकल्प चुनाव और जीत भी हासिल की। मैंने प्रत्येक चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र बदले थे, परन्तु किस्मत मेरे साथ रही। पिछले 15 वर्षों में मैंने देखा कि भाजपा निरन्तर म्युनिसिपिल क्षेत्रों में ताकत बन कर उभरती रही। जब मैंने 2000 में चुनाव लड़ा, उस समय पार्टी के पास केवल 15 सीटें थी। 2005 में यह बढ़कर 17 हो गई, परन्तु 2010 में गिरकर 15 पर पहुंच गई। इस बार, भाजपा ने म्युनिसिपिलिटी की 52 सीटों में से 24 सीटें जीतीं हैं। हम तिकोनी लड़ाई में कहीं ज्यादा ऊपर उठकर आए हैं।

श्रीमती शशिधरन ने आगे कहा कि पलक्कड़ भाजपा की सिविक बॉडी का शोपीस बन गया है। पार्टी का म्युनिसिपिल गवर्नेंस में बहुत बड़ा दाव लगा हुआ है, क्योंकि अप्रैल में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। विकास योजनाएं शुरू कर हम और अधिक लोगों के पास पहुंचेंगे। पार्टी और म्युनिसिपिल कौंसिल को विधानसभा चुनाव मिल कर लड़ने होंगे। ■

सर्बानंद सोनोवाल असम भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 21 नवंबर को केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को असम प्रदेश अध्यक्ष तथा चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया। विदित हो कि अगले साल असम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

श्री सोनोवाल फिलहाल केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। वे केंद्र सरकार में स्थान पाने से पहले भाजपा असम प्रदेश के अध्यक्ष थे।

वह ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष और असम गण परिषद् के नेता रह चुके हैं। वर्तमान असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य का कार्यकाल अक्तूबर में खत्म हो गया था। उपरोक्त घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि श्री हेमंत विश्व शर्मा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक होंगे।

श्री जावडेकर ने कहा कि श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं।

वहीं सांसद श्री रामेन डेका और श्री राजेन गोहैन के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के तीन उपाध्यक्षों में एक होंगे।

श्रीमती बिजयो चक्रवर्ती, श्री कामख्या ताशा, डॉ. राजदीप राय, श्री विजय गुप्ता और मोहम्मद अवाल चुनाव समिति के सदस्य हैं।

श्री जावडेकर ने कहा कि असम बदलाव के लिए तैयार है और स्थानीय चुनाव में भाजपा की जीत उसकी मजबूत स्थिति का सबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में जिस तरह शासन किया, उससे समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है।

संभाला प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार

केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 25 नवम्बर को हेंगराबाड़ी स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में निवर्तमान अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की प्रदेश इकाई अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला। इस मौके पर पार्टी के सांसद, विधायक, पार्टी के सभी मोर्चा के प्रमुखों ने उन्हें गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद इस मौके पर श्री सोनोवाल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी है। ■

सरकार की उपलब्धियां

15 प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई और भी आसान

हालिया वर्षों में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार

केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार ने रेलवे, मेडिकल उपकरण, बीमा, निर्माण, रक्षा, सिंगल ब्रांड रिटेल, बैंकिंग समेत 15 सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की प्रक्रिया को आसान बनाने की घोषणा की है। सरकार अपने इस कदम से देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाना चाहती है। सरकार ने ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49 फीसदी तक करने का निर्णय लिया है। वहीं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से एफडीआई की सीमा 3000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दी गई है। वहीं, इससे ऊपर के प्रस्तावों के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेना जरूरी होगा।

इन दिनों भारत दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्रों के बीच सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक ने 'कारोबार करने में सुगमता' से जुड़े अध्ययन, 2016 में भारत की रैंकिंग में 12 पायदानों का इजाफा किया है। एफडीआई में 40 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनेक वैश्विक संगठनों ने भारत को पूरी दुनिया में एफडीआई के लिहाज से सबसे आकर्षक देश बताया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को 'सबसे चमकीला राष्ट्र' बताया है। वहीं, विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर 7.5 फीसदी या उससे भी ज्यादा रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

भाजपानीत राजग सरकार के सत्ता में आने के साथ ही श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास (भारत को एक विकसित राष्ट्र में तब्दील करना) और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत के विकास की रफ्तार बढ़ाने में वित्तीय संसाधन सबंधी बाधाओं के मद्देनजर अनेक आर्थिक सुधारों के साथ-साथ देश में कारोबार करने को और ज्यादा आसान बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। लंबे समय से अटकी पड़ी अनेक परियोजनाओं की राह की बाधाएं समाप्त करने के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन में तेजी भी लाई गई है। इसके अच्छे नतीजे भी अब नजर आने लगे हैं।

एफडीआई में सुधार

मुख्य बातें

- निर्माण, रीयल एस्टेट, रक्षा, ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनियों (एएलपी) में एफडीआई नीति में ढील।
- रबड़, कॉफी, इलायची, पाम आयल व जैतून की बागवानी में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति।
- सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार में एफडीआई नीति में ढील।
- कंपनियों को ई-कॉमर्स के जरिये उत्पाद बेचने की अनुमति।
- क्षेत्रीय विमानन सेवाओं में ऑटोमैटिक रूट से 49 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति।

देश के लाखों युवाओं को लाभकारी रोजगार या उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसे अभियान शुरू किए। इस कड़ी की ताजा पहल 'स्टार्ट-अप इंडिया' है। निवेश के इस पूरे माहौल को और बेहतर बनाने एवं देश में विदेशी निवेश लाने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था के 15 प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) सुधार लागू किए हैं।

जिन 15 सेक्टरों में एफडीआई के नियम आसान हुए हैं, वो हैं, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग एंड ड्यूटी फ्री शॉप्स, सिविल एविएशन, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर कैश एंड कैरी, होलसेल ट्रेडिंग, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एंड अप्रूवल से जुड़ी शर्तें, एनआरआई के स्वामित्व व नियंत्रण वाली कंपनियों द्वारा किया जाना वाला निवेश, भारतीय कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण का ट्रांसफर और

स्थापना, कृषि और पशुपालन, पौधारोपण, माइनिंग एंड मिनरल, डिफेंस, और ब्रॉडकास्टिंग। एक साथ कई क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने से देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आने का रास्ता खुल गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय से आर्थिक विकास में तेजी आने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

राजग सरकार ने अपने बयान में कहा कि इन सुधारों से देश में विदेशी निवेश की प्रक्रिया को और आसान, युक्तिसंगत और सरल बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई प्रस्ताव गवर्नमेंट रूट के बजाय ऑटोमैटिक रूट से आएं, जिससे निवेशकों की ऊर्जा और समय दोनों की बचत होगी। इन एफडीआई सुधारों से कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, रक्षा, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन और निर्माण जैसे सेक्टर को फायदा होगा। बयान में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ता अन्य देशों से आयात के बदले देश में बने उत्पाद ही खरीदेंगे।

एफआईपीबी की सीमा भी बढ़ी

प्रस्तावित सुधारों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की सीमा भी 3000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की गई है। अब एफआईपीबी 5000 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है, इससे पहले यह सीमा 3000 करोड़ रुपए थी। इससे ज्यादा के एफडीआई प्रस्तावों पर केंद्रीय कैबिनेट विचार करती थी और मंजूरी देती थी। अब 5000 करोड़ रुपए से अधिक के एफडीआई प्रस्तावों पर ही कैबिनेट विचार करेगी।

रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को 49 फीसदी तक विदेशी निवेश के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि 49 फीसदी से ज्यादा के विदेशी निवेश के लिए भी नियम आसान कर दिए गए हैं। अब 49 फीसदी से ज्यादा की विदेशी निवेश के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधीन एफआईपीबी की अनुमति काफी है। अगर विदेशी निवेश की रकम 5 हजार करोड़ रुपए से कम है, तो एफआईपीबी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश के कई प्रस्ताव सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी की अनुमति के इंतजार में सालों अटके रह जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा क्षेत्र में तभी निवेश आएगा जब तक कि रक्षा उत्पाद का कोई बाजार होगा। भारत में कोई भी विदेशी कंपनी निर्यात करने के लिए निवेश तो कोई करेगा नहीं। भारत में रक्षा मंत्रालय ही एकमात्र बड़ा खरीदार है। छोटे मोटे हथियार के लिए गृह मंत्रालय है लेकिन बड़ा खरीदार रक्षा मंत्रालय है। जब तक भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से निवेश के उत्पाद खरीदने का आश्वासन नहीं मिलता तब तक समस्या बनी रहेगी।

रक्षा क्षेत्र के अलावा भारत ने कॉफी, रबर और पाम ऑयल सेक्टर में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है। ब्राडकॉस्टिंग, केबल, डीटीएच, मोबाइल टीवी में भी विदेशी कंपनियां 100 फीसदी तक निवेश कर सकती हैं। सिंगल ब्रांड रीटेल कंपनियों को ई कॉमर्स कारोबार करने के लिए अलग कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। निर्माण और खनन क्षेत्र में कई नियमों को हटाया गया है। विदेशी कंपनियां भारत में खबरों से जुड़े चैनलों में इजाजत के साथ 49 फीसदी तक निवेश कर सकती हैं जबकि खबरों के अलावा बाकी चैनलों में 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। केंद्र की राजग सरकार के मुताबिक यह हाल के वर्षों में लिया गया सबसे बड़ा आर्थिक सुधार का फैसला है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है।

गौरतलब है कि भारत में अप्रैल-जून 2015 तिमाही में 19.39 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 29.5 फीसदी ज्यादा है। सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, मेडिकल डिवाइस, इंश्योरेंस, पेंशन, निर्माण और रक्षा जैसे क्षेत्रों में एफडीआई पहले ही खोल दिया है।■

प्रस्तावित सुधारों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की सीमा भी 3000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की गई है। अब एफआईपीबी 5000 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दे सकता है, इससे पहले यह सीमा 3000 करोड़ रुपए थी। इससे ज्यादा के एफडीआई प्रस्तावों पर केंद्रीय कैबिनेट विचार करती थी और मंजूरी देती थी। अब 5000 करोड़ रुपए से अधिक के एफडीआई प्रस्तावों पर ही कैबिनेट विचार करेगी।

सरकार की उपलब्धियां

जन धन खाता योजना में 19 करोड़ नए खाते खुले

इन खातों में 27 हजार करोड़ रुपये जमा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई जनधन योजना को देश से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना के तहत शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर किसी को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने में मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना को पिछले वर्ष में सितम्बर माह के दौरान लांच किया गया था और हर तरफ इस योजना को लेकर काफी अच्छा रुझान भी देखने को मिला था। इस योजना के शुरू किये जाने के बाद से अब तक जीरो बैलेंस एकाउंट्स का बैंकिंग इंडस्ट्री में हिस्सा 77 फीसदी से 36 फीसदी पर आ गया है। इस दौरान ही यह भी देखने में आया है कि जन धन खाता योजना के अंतर्गत 19 करोड़ नए खाते खोले गए है, और इन खातों में अभी तक करीब 27 हजार करोड़ रुपये रखे हुए है। जबकि बात करे एक साल पहले कि तो तब 5.37 करोड़ बैंक खातों में सिर्फ 4.27 लाख रुपये देखने को मिले थे। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा है कि जीरो बैलेंस एकाउंट्स की संख्या में कमी आ रही है और यह एक अच्छा संकेत भी साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इसके द्वारा महिलाओं की घरेलू फैसले करने की शक्ति में भी इजाफा होना है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पहले बैंक एकाउंट्स में बैलेंस 250 रुपये तक हुआ करता था अब वह 2500 रुपये तक पहुँच गया है। यह भी देखने में आ रहा है कि हर महीने इन एकाउंट्स में कम से कम एक ट्रांसेक्शन हो रहा है। इसके चलते यह बात भी सामने आई है कि अगस्त 2014 से लेकर मई 2015 के माह अंतराल में चालू खातों की संख्या भी 25 गुना हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में भी इन खातों को खोले जाने से काफी इजाफा देखने को मिला है।

ग्रामीण इलाकों में जहाँ पहले बैंक एकाउंट्स में बैलेंस 250 रुपये तक हुआ करता था अब वह 2500 रुपये तक पहुँच गया है। यह भी देखने में आ रहा है कि हर महीने इन एकाउंट्स में कम से कम एक ट्रांसेक्शन हो रहा है। इसके चलते यह बात भी सामने आई है कि अगस्त 2014 से लेकर मई 2015 के माह अंतराल में चालू खातों की संख्या भी 25 गुना हो चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 'पूर्वी भारत से रेमिटेंस बढ़ने और पश्चिमी भारत की ओर ज्यादा कैश डिपॉजिट्स के कारण जीरों एकाउंट में कमी आई है। यह अच्छा संकेत है। इससे घरेलू फैसले करने की महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी। दरअसल सेविंग डिपॉजिट बैलेंस के साथ बैंक अब अच्छी रकम वाले खातेदारों को नए प्रॉडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने यहां खोल गए जनधन खातों की रैंडम सैंपल स्टडी की थी। सर्वे से पता चला कि देश के हर हिस्से में एक्टिव एकाउंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। सक्रिय खातों में हर महीने औसतन एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगस्त 2014 से मई 2015 के बीच सक्रिय खातों की संख्या 25 गुनी हो गई।

पश्चिम भारत के ग्रामीण में ऐसे सक्रिय खाते सबसे तेजी से बढ़े। इसके बाद उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों का नंबर रहा। पूर्वी और दक्षिण भारत के कस्बाई इलाकों में भी अच्छी प्रगति देखी गई। एसबीआई ने 'एक्टिव ऑफ एक्टिव' एकाउंट्स की एक कैटेगरी भी बनाई, जिसमें लेन-देन ज्यादा हो रहे थे। दरअसल, डिपॉजिट बैलेंस बढ़ने और ट्रांजैक्शन की संख्या में इजाफा होने से ये खाते आने वाले समय में लाभकारी हो सकते हैं, खासतौर से तब जब इस बैलेंस से क्रेडिट प्रॉडक्ट्स को वृद्धि मिले। ■

वैचारिकी

अब्दुल्ला द्वारा जुलाई समझौते का उल्लंघन स्वतंत्र कश्मीर की रूपरेखा तैयार

– दीनदयाल उपाध्याय

जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ प्रारंभ से ही कश्मीर के मुद्दे पर अपने राष्ट्रवादी अभिमत के लिए जानी जाती रही है। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने इसके लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। आजादी के पश्चात्, कश्मीर में लड़ाई की स्थिति होने के कारण संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर भारत के साथ उसका संबंध जोड़ा गया, लेकिन यह भी प्रावधान किया गया कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह तबसे जारी है और आज राष्ट्रीय एकता की राह में रोड़ा बना हुआ है। उस समय शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र कश्मीर के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियों के चलते उनका यह मंसूबा पूरा नहीं हो सका। जनसंघ के तत्कालीन महामंत्री और विचारक राजनेता पं. दीनदयाल उपाध्याय ने 11 मई 1953 को पांचजन्य में इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए लेख लिखा था। प्रस्तुत है लेख का प्रथम भाग:

अलग निशान और अलग प्रधान का निर्माण कर जम्मू और कश्मीर के नेता अपनी पृथकतावादी मनोवृत्ति का परिचय पहले ही दे चुके हैं किंतु जो अलग विधान इस राज्य के लिए उन्होंने बनाने का प्रस्ताव किया है। वह इस मनोवृत्ति का व्यापक स्पष्टीकरण करता है। सच में तो भारत के लिए जम्मू और कश्मीर भी उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के पूर्व स्वतंत्र की हुई शेष पाँच सौ चव्वन रियासतें हैं। एक विधान बन चुका है। वह विधान सब पर लागू है और आशा थी कि जम्मू और कश्मीर पर भी यह विधान लागू होगा। किंतु न मालूम किस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के मुँह से जनमत संग्रह की बात निकल गई और तब से शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथी उसका आधार लेकर स्वतंत्र कश्मीर के मंसूबे पूरे कर रहे हैं। कश्मीर में लड़ाई की स्थिति होने के कारण उस रियासत का भारत के साथ अन्य रियासतों के समान पूरी तरह से विलीनीकरण नहीं हो सका और इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़कर भारत कश्मीर के उस समय के संबंधों का दिग्दर्शन कराया गया तथा भावी की दिशा इंगित की गई।

अस्थायी और अंतरिम प्राविधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 370 में यह स्पष्ट दिया है कि भारत और कश्मीर के संबंध तीन मामलों तक सीमित रहेंगे। किंतु उसी अनुच्छेद की धारा 3 में यह भी कहा है कि कश्मीर की संविधान सभा के अभिस्ताव पर भारत के प्रधान यह घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 पूरी तरह समाप्त हो गया अथवा उसमें कुछ परिवर्तन कर लिया गया। विधान निर्माताओं की यह अपेक्षा थी कि उस समय चाहे कश्मीर को अन्य 'ख' श्रेणी राज्यों के समकक्ष न रखा जाए किंतु वह दिन अवश्य आएगा जब अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाएगा और कश्मीर भी पूर्णतया 'ख' श्रेणी का राज्य होकर भारत में मिल जाएगा। स्वर्गीय श्रीयुत गोपालास्वामी आयंगर ने, जिन्होंने अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव किया था, संविधान सभा में यह आशा भी व्यक्त की थी किंतु वह आशा दुराशा ही सिद्ध हुई। शेख अब्दुल्ला और उनके साथी, जिन्हें हमने भारतीय समझा था, भारतीय नहीं बन पाए। वे स्वत: को कश्मीरी ही समझते हैं और उससे ऊपर उठने को तैयार नहीं।

धीरे-धीरे जब यह प्रकट होने लगा कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर को भारत में पूरी तरह नहीं मिलाना चाहते हैं तो भारत में उनके विरुद्ध जनमत ने जोर पकड़ा। यहाँ तक कि रणवीर सिंह पुरा में स्वतंत्र कश्मीर का प्रस्ताव करते हुए जो भाषण शेख अब्दुल्ला ने दिया, उसकी निंदा पं. नेहरू ने भी की। उनके मंसूबों के इस प्रकार साफ प्रकट होने पर भारत सरकार ने उन्हें बुलाया और यह जानना चाहा कि आखिर वे कश्मीर का कौन सा अंतिम स्वरूप रखना चाहते हैं। छोटे-छोटे मामलों

में चाहे कश्मीर में भिन्न प्रकार का शासन हो, किंतु भारतीय संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, वित्तीय एकीकरण, निर्वाचन, प्रधान के संकटकालीन अधिकार आदि तो सभी जगह पर समान रूप से लागू होने चाहिए। फलतः जुलाई 1952 में नेहरूजी तथा शेख अब्दुल्ला के बीच बातचीत हुई जिसके अनुसार उपर्युक्त सभी विषयों को किसी-न-किसी अंश में कश्मीर पर लागू करने का निर्णय हुआ। इस जुलाई समझौते को उस समय नेहरूजी ने बहुत संतोषजनक बताया था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इस प्रकार भारत का संविधान पूरी तरह नहीं तो कम-से-कम कुछ अंशों में तो कश्मीर पर अवश्य लागू हो जाएगा। किंतु राजनीतिक दृष्टि से यह समझौता भारी भूल हुई क्योंकि इसमें कश्मीर की एक स्वतंत्र सत्ता किसी-न-किसी रूप में मान ली गई। अभी तक जो अनिश्चित थी वह निश्चित हो गई। और उसका लाभ शेख अब्दुल्ला ने 'अंगुली के बाद पहुंचा पकड़ने' की नीति के अनुसार उठाया है।

अब्दुल्ला की इस नीति को समझने के पूर्व हमें कश्मीर राज्य के लिए वहाँ की संविधान समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप का थोड़ा सा दिग्दर्शन करना पड़ेगा

प्रारूप के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य भारत की एक स्वायत्त संबद्ध इकाई (Autonomous Federated Unit) होगा और वह सर्वप्रभुता संपन्न राज्य रहेगा। उसकी वैधानिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक शक्तियों का स्रोत न तो भारत की जनता या संविधान है बल्कि कश्मीर की जनता और उसका अपना संविधान है।

प्रारूप का भाग 2 नागरिकता से संबंध रखता है जिसके अनुसार 'स्थायी निवासी' की संज्ञा देकर कश्मीरवासियों को भारत के नागरिकों से भिन्न नागरिकता प्रदान की गई है।

भाग 3 मूलभूत अधिकारों से संबंध रखता है जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 के सभी मूलभूत अधिकार सम्मिलित कर लिए गए हैं। किंतु भूमि सुधारों के लिए मुआवजे आदि से बचत का मार्ग भी निकाल लिया है। कश्मीर में स्थायी संपत्ति खरीदने अथवा नौकरियों में स्थान प्राप्त करने का अधिकार केवल कश्मीर के 'स्थायी निवासियों' को ही दिया गया है। मौलिक अधिकारों के साथ भारतीय संविधान से भिन्न और संभवतया किसी भी संविधान की दृष्टि से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी किया है जिसके अनुसार एक सेकुलर प्रजातंत्रीय राज्य का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि (क) वह जातीय तथा सांप्रदायिक एकता स्थापित करें, (ख) सभी सार्वजनिक कार्यों में प्रामाणिकता का परिचय दें, (ग) अपने व्यवहार में गौरव, शालीनता और उत्तरदायित्व को प्रकट करें, (घ) किसी भी सार्वजनिक संस्था में सोच समझकर तथा ईमानदारी से वोट दें, (च) सांप्रदायिक विद्वेष का प्रचार न करें, (छ) चोर-बाजारी और मुनाफाखोरी या इसी प्रकार के समाज विरोधी काम न करें। उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन न करने वालों को मताधिकार से वंचित किया जा सकेगा।

भाग 4 जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रमुख, जो सदरे रियासत कहलाएगा के निर्वाचन, कर्तव्य आदि का वर्णन करता है। केवल स्थायी नागरिक ही सदरे रियासत चुने जा सकेंगे। सदरे रियासत को (खुदा) का नाम लेकर, चाहे वह नास्तिक ही क्यों न हो, शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। सदरे रियासत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उनकी प्रसादावधि तक पदारूढ़ रहेगा किंतु उसकी नियुक्ति कश्मीर की राष्ट्रीय सभा दोषारोपण (Impeachment) कर उसे हटा भी सकती है। भारत के राष्ट्रपति को तो राष्ट्रीय सभा के निर्णयों पर मुहर लगाने मात्र का अधिकार है। यदि मुहर नहीं लगाई तो क्या परिणाम होगा, यह भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है।

कश्मीर का शासन-कार्य एक मंत्री परिषद् के द्वारा होगा जो सामूहिक रूप से राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद् प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार सदरे रियासत द्वारा नियुक्त की जाएगी और उसकी इच्छा के अनुसार ही एक या अधिक मंत्री हटाए भी जा सकते हैं।

राष्ट्रीय महासभा कश्मीर की विधान परिषद् होगी जोकि प्रति चालीस हजार निवासियों के ऊपर एक सदस्य के आधार पर चुनी जाएगी। केवल जम्मू प्रांत में हरिजनों के लिए पाँच वर्ष के लिए चार स्थान सुरक्षित रहेंगे। कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिकों से अधिक समझदार है इसलिए उन्हें अठारह वर्ष की उम्र में ही मताधिकार प्राप्त हो जाएगा।

मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार (Recall) दिया है। महासभा का सब कार्य उर्दू में होगा। अध्यक्ष यदि चाहे तो किसी भी सदस्य को अंग्रेजी में और यदि वह अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता तो मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

क्रमशः...

श्रद्धांजलि

अशोक सिंहल नहीं रहे

श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विहिप के वास्तुकार श्री अशोक सिंघल का 17 नवंबर को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया।

नब्बे के दशक में श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन जब उफान पर था, उन दिनों जिनकी सिंह गर्जना से लोगों के हृदय हर्षित हो जाते थे, ऐसे श्री अशोक सिंहल विहिप के आधारस्तंभ थे पर वे जीवन भर स्वयं को संघ का एक समर्पित प्रचारक ही मानते रहे।

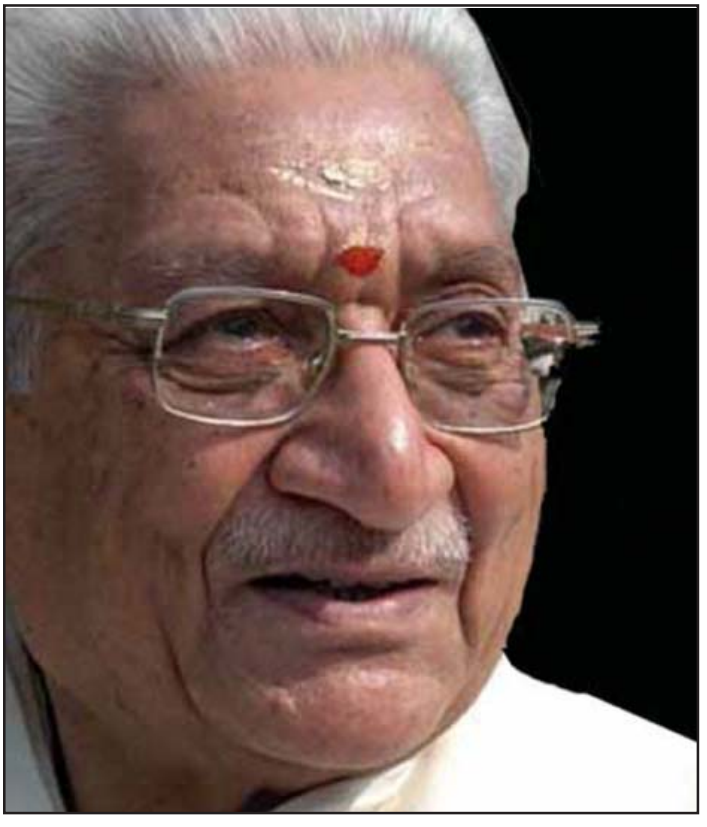

श्री अशोक सिंहल का जन्म आश्विन कृष्ण पंचमी (27 सितम्बर, 1926) को उ.प्र. के आगरा नगर में हुआ था। उनके पिता श्री महावीर सिंहल शासकीय सेवा में उच्च पद पर थे। घर के धार्मिक वातावरण के कारण उनके मन में बालपन से ही हिन्दू धर्म के प्रति प्रेम जाग्रत हो गया। उनके घर संन्यासी तथा धार्मिक विद्वान आते रहते थे। कक्षा नौ में उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती की जीवनी पढ़ी। उससे भारत के हर क्षेत्र में सन्तों की समृद्ध परम्परा एवं आध्यात्मिक शक्ति से उनका परिचय हुआ। 1942 में प्रयाग में पढ़ते समय प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) ने उनका सम्पर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कराया। उन्होंने अशोक जी की माता जी को संघ के बारे में बताया और संघ की प्रार्थना सुनायी। इससे माता जी ने अशोक जी को शाखा जाने की अनुमति दे दी।

बाद में उन्होंने अपना जीवन संघ कार्य हेतु समर्पित करने का निश्चय कर लिया। बचपन से ही अशोक जी की रुचि शास्त्रीय गायन में रही है।

1948 में संघ पर प्रतिबन्ध लगा, तो अशोक जी सत्याग्रह कर जेल गये। वहाँ से आकर उन्होंने काशी हिन्दू विश्व विद्यालय से बी.ई. मेटॅलर्जी अंतिम वर्ष की परीक्षा दी और प्रचारक बन गये। अशोक जी की सरसंघचालक श्री गुरुजी से बहुत घनिष्ठता रही। प्रचारक जीवन में लम्बे समय तक वे कानपुर रहे। यहाँ उनका सम्पर्क श्री रामचन्द्र तिवारी नामक विद्वान से हुआ।

वेदों के प्रति उनका ज्ञान विलक्षण था। अशोक जी अपने जीवन में इन दोनों महापुरुषों का प्रभाव स्पष्टत: स्वीकार करते हैं।

1975 से 1977 तक देश में आपातकाल और संघ पर प्रतिबन्ध रहा। इस दौरान अशोक जी इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध हुए संघर्ष में लोगों को जुटाते रहे। आपातकाल के बाद वे दिल्ली के प्रान्त प्रचारक बनाये गये।

1981 में डा. कर्णसिंह के नेतृत्व में दिल्ली में एक विराट हिन्दू सम्मेलन हुआ पर उसके पीछे शक्ति अशोक जी और संघ की थी। उसके बाद अशोक जी को विश्व हिन्दू परिषद् के काम में लगा दिया गया।

इसके बाद परिषद् के काम में धर्म जागरण, सेवा, संस्कृत, परावर्तन, गोरक्षा.. आदि अनेक नये आयाम जुड़े। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आन्दोलन, जिससे परिषद् का काम गाँव-गाँव तक पहुँच गया। इसने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा बदल दी। भारतीय इतिहास में यह आन्दोलन एक मील का पत्थर है। आज वि.हि.प. की जो वैश्विक ख्याति है, उसमें अशोक जी का

योगदान सर्वाधिक है।

अशोक जी परिषद् के काम के विस्तार के लिए विदेश प्रवास पर जाते रहे हैं। इसी वर्ष अगस्त-सितम्बर में भी वे इंग्लैंड, हालैंड और अमरीका के एक महीने के प्रवास पर गये थे। परिषद् के महासचिव श्री चम्पत राय जी भी उनके साथ थे।

गत 18 नवंबर को भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कई नेताओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निगम बोध घाट पर श्री अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार किया गया।

श्री सिंघल के भतीजे सलिल ने सिंघल के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सलिल दिवंगत विहिप नेता के बड़े भाई प्रमोद का बेटा है।

इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री जेपी नड्डा, डॉ. हषवर्धन, सुश्री उमा भारती, श्री अनंत कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, गुजरात के राज्यपाल श्री ओ.पी. कोहली और बिहार भाजपा के नेता श्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे।

इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित संघ कार्यालय में भी रखा गया, जहां पर भाजपा और विहिप के नेताओं समेत अन्य लोग उनके अंतिम दर्शन किए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह सहित कई नेताओं और मंत्रियों ने श्री अशोक सिंघल के निधन पर शोक जताया। ■

शोक संदेश

अशोक सिंघलजी का निधन गहरी निजी क्षति है। वह अपने आप में एक संस्था थे जिन्होंने आजीवन देश की सेवा की। मेरा सौभाग्य है कि अशोकजी का मुझे हमेशा आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। उनके परिवार और अनगिनत समर्थकों को मेरी संवेदनाएं। अशोक सिंघल कई अनूठी चीजों और सामाजिक कार्यों के प्रेरणास्रोत थे जिनका फायदा गरीबों को मिला। वह पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं।

– ***नरेंद्र मोदी,*** *प्रधानमंत्री, भारत सरकार।*

एक अतिसंपन्न परिवार में जन्म के बावजूद, युवा अवस्था में ही सब कुछ त्याग कर संघ के प्रचारक के रूप में राष्ट्र सेवा में निकले और आजीवन एकनिष्ठ प्रचारक रहे। वह विश्व हिन्दू परिषद् में अस्सी के दशक की शुरुआत से मृत्युपर्यंत अलग-अलग पद पर कार्यरत रहे और रामजन्मभूमि आन्दोलन, रामसेतु आन्दोलन और धर्म जागरण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। माननीय अशोक जी का पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित रहा। सादगी, साहस, धर्म-निष्ठा और उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति जैसे गुणों से पल्लवित एक सिद्धांतवादी जीवन का आज अंत हो गया। रामजन्मभूमि आन्दोलन, विश्व हिंदू परिषद् और समस्त राष्ट्र के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। मैं करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसी दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ।

– ***अमित शाह,*** *राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा*

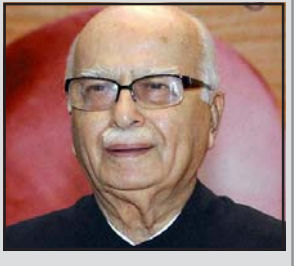

मैं श्री अशोक सिंघल के निधन से स्तब्ध हूं। श्री सिंघल 20 साल से अधिक समय तक विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे और रामजन्मभूमि आंदोलन के मुख्य वास्तुकार थे। मुझे कई मौके पर उनके साथ बात करने का सौभाग्य मिला। वह बहुत ही ज्ञानी एवं प्रतिबद्ध आदर्शों वाले व्यक्ति थे। मैं अशोक सिंघल के निधन पर संवेदना जताता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

– ***लालकृष्ण आडवाणी,*** *पूर्व उपप्रधानमंत्री, भारत सरकार।*

वे एक 'आधुनिक संत' थे और उनके निधन से हमने संत सरीखा इंसान खो दिया।

– ***सुमित्रा महाजन,*** *लोकसभा अध्यक्ष*

प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा

ब्रिटेन के साथ 14 अरब डॉलर का समझौता

असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12-14 नवंबर की तीन दिवसीय ब्रिटेन यात्रा अत्यंत सफल रही। साथ ही यह पहली बार है ब्रिटिश संसद को किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया हो। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्यमों के बीच 14 अरब डॉलर के समझौते हुए। साथ ही द्विपक्षीय बातचीत के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग प्रमुख मुद्दा रहा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्यमों के बीच 14 अरब डॉलर के समझौते हुए। इसमें ब्रिटेन की ओपीजी पावर वेंचर्स कंपनी द्वारा अगले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में 4,200 मेगावाट क्षमता की नई विद्युत सृजन इकाई में 4.4 अरब डॉलर की निवेश योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन के बीच लगभग दो दर्जन निवेश समझौते हुए, जिसमें मर्लिन एंटरटेनमेंट 2017 तक नई दिल्ली में मैडम तुसाद मोम संग्रहालय खोलेगा। इसके साथ ही वोडाफोन भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियानों को मदद देने के लिए 1.4 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

इसके अलावा, यूरोप की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी लाइटसोर्स का कहना है कि वह भारत में अगले पांच साल में भारतीय कंपनियों की साझेदारी में तीन गीगावाट सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचागत इकाई के डिजाइन, स्थापना और प्रबंधन के लिए लगभग तीन अरब डॉलर का निवेश करेगी। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 9.2 अरब पाउंड (14 अरब डॉलर) के व्यावसायिक समझौते हुए।

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञता साझा करने और कारोबार समझौतों के जरिये भारत की महत्वाकांक्षी शहरी विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए तीन भारतीय शहरों इंदौर, पुणे और अमरावती के साथ साझेदारी की। स्वच्छ नदी प्रणाली के लिए टेम्स-गंगा साझेदारी शुरू करने का भी ऐलान किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लंदन बाजार का वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पहले से ज्यादा इस्तेमाल

करने जा रहे हैं और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लंदन में रेलवे रुपया बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं। यह इस लिहाज से भी उपयुक्त होगा कि भारतीय रेलवे की शुरुआत ब्रिटेन में ही हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को काफी महत्व देता है। इसमें नियमित सैनिक अभ्यास और रक्षा व्यापार एवं सहयोग भी शामिल है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन ने दोनों देशों के संबंधों को 'नई गतिशील आधुनिक भागीदारी' करार दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये अपने देश का समर्थन दोहराया। श्री कैमरन ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण का वित्तपोषण करने में पहले नंबर के भागीदार बनना चाहते हैं और लंदन को विदेशों में रुपये में कारोबार का केन्द्र बनाना चाहते हैं। इसके लिये सरकार समर्थित पहले रुपया अंकित बॉन्ड सहित एक अरब के बॉन्ड जारी किये जाएंगे। कैमरन ने कहा कि हम अधिक महत्वाकांक्षी व आधुनिक भागीदारी कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत पूरे यूरोपीय संघ के देशों में जितना निवेश करता है, उसके कुल योग से कहीं अधिक ब्रिटेन में निवेश करता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत करने के लिये कैमरन अपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय से बाहर निकले। इसके बाद दोनों नेता दुनिया के इस सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यालय में चले गये जहां उन्होंने 90 मिनट तक बातचीत की। उल्लेखनीय है कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में ब्रिटेन का 18वां स्थान है। वर्ष 2014-15 में द्विपक्षीय व्यापार 14.34 अरब डॉलर रहा। भारत में निवेश करने वाले देशों में ब्रिटेन तीसरा बड़ा निवेशक है।

असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन के बीच लंदन में हुई द्विपक्षीय बातचीत में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इससे वर्ष 2022 तक भारत के हर घर को चौबीसों घंटे बिजली देने के मोदी सरकार के महत्वूपर्ण वादे को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के बाद से लगातार भारत और ब्रिटेन के बीच नागरिक परमाणु सहयोग पर बातचीत हो रही है।

श्री कैमरन व्यक्तिगत तौर पर भारत के साथ परमाणु करार के समर्थक हैं और वह इस बारे में कई बार बयान दे चुके हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि असैन्य परमाणु समझौता होना हमारे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के हमारे संकल्प का प्रतीक है। भारत के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी वैश्विक केन्द्र में सहयोग का समझौते से वैश्विक परमाणु उद्योग में सुरक्षा और बचाव को मजबूती मिलेगी।

भारत को दुनिया की मेहरबानी नहीं, बराबरी चाहिए: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की मेहरबानी नहीं चाहता है बल्कि वह बराबरी चाहता है और

पिछले 18 महीनों में यह शुभ संकेत सामने आने लगा है कि आज भारत से जो भी बात करता है वह बराबरी से बात करता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वेम्ब्ले स्टेडियम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन और विशाल संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों की उपस्थिति में 13 नवंबर को कहा कि दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। भारत दुनिया से मेहरबानी नहीं चाहता। भारत दुनिया से बराबरी चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने के अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूं कि आज जो भी भारत से बात करता है, बराबरी से बात करता है। उल्लेखनीय है कि 18 महीने पहले मोदी के नेतृत्व में भारत में राजग सरकार सत्ता में आई थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की विशाल विविधता इसकी अपनी विशेषता, गौरव और ताकत में है। एक घंटे से अधिक समय तक चले अपने भाषण में भारत के विजन की व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री ने अलवर राजस्थान के रहने वाले इमरान खान का जिक्र किया, जिसने लगभग 50 शिक्षा एप तैयार करके उन्हें मुफ्त वितरित किया। उन्होंने

हरियाणा के एक सरपंच को भी स्मरण किया, जिसने उनके बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आह्वान की प्रतिक्रिया में बेटी के साथ सेल्फी सहित इस अभियान में भाग लिया, जो वैश्विक रूप से सफल हुई।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के सभी प्रमुख धर्म भारत में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारतवंशी इन मूल्यों को अपने साथ जहां जाते हैं वहीं ले जाते हैं। इसलिए वे भारत के महान दूत हैं।

प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा पर अपनी विशेष योजनाओं और अपनी सरकार की अब तक की पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रचुर मात्रा में सौर विकिरण से संपन्न देशों के साथ वैश्विक ''सौर गठबंधन'' का नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत आप टीवी के पर्दों और समाचार पत्रों की सुर्खियों में देखते हैं वह उससे कहीं बड़ा और अधिक महान है।

श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर देश भारत से जुड़ना चाहता है लेकिन अब वह 'विन-विन' के फामूर्ले के साथ जुड़ना चाहता है। आगे बढ़ना चाहता है तो कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहता है। और मैं इसे आने भविष्य के शुभ संकेत के रूप में देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत ने जो गति और दिशा पकड़ी है, भारत और दुनिया के लोग बहुत जल्दी उसके फल को भी देखना शुरू कर देंगे।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 18 महीने के अपने अनुभवों से मैं कह सकता हूं कि भारत को अब गरीबी में रहने का कोई कारण नहीं है। हमने बिना कारण गरीबी को पाल रखा है। आदतन हमें गरीबी को पुचकारने में मजा आने लग गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन सवा सौ करोड़ आबादी वाले जिस देश में 80 करोड़ लोग 35 साल से कम उम्र के हों, यानी जो देश जवानी से लबालब भरा हो, वह देश अब पीछे नहीं रह सकता है, वह विकास की इस यात्रा में रूक नहीं सकता।

इस अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन ने श्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ब्रिटेन में भारतीयों का बड़ा योगदान है और वह दिन दूर नहीं जब एक इंडियन ब्रिटिश, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। श्री मोदी के 'अच्छे दिन..' के नारे का जिक्र करते हुए श्री कैमरन ने कहा कि किसी को भरोसा नहीं था कि एक चायवाला विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया। अच्छे दिन आने वाले है. .उनकी यह जो दृष्टि है, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे दिन जरूर आयेंगे।

मोदी द्वारा बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण तथा अम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंदन के लैम्बेथ में बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें कल पेरिस में हुए आतंकी हमले के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यह केवल फ्रांस के लोगों पर हमला नहीं था, बल्कि पूरी मानवता पर हमला था और अब समय आ गया है कि इस वैश्विक त्रासदी का मुकाबला करने के लिए विश्व के सारे मानवतावादी बल एकजुट हों। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद को परिभाषित किया है।

प्रधानमंत्री ने श्री बसवेश्वर को महान दार्शनिक और समाज सुधारक बताया, जिन्होंने अपने समय में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जमीनी स्तर पर जनतंत्र की मजबूती के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री ने लंदन में किंग हैनरीज मार्ग पर डॉ. अम्बेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। उन्होंने डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती प्रज्जवलित की। उन्होंने स्मारक पट्टिका का अनावरण भी

किया। प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, ''यह एक पवित्र स्थान है, जहां डॉ. अम्बेडकर ने ज्ञानवर्द्धन किया, कठिनाइयों को दूर किया और उनके सामने आने वाली बाधाओं को पार किया।'' उन्होंने कहा, ''मैं उस महान व्यक्ति को नमन करता हूं, जिसने समाज के दलित वर्गों के लिए निरंतर कार्य किया।'' प्रधानमंत्री ने सोलिहुल में जगुआर-लैंड रोवर निर्माण इकाई का दौरा भी किया।

सीईओ फोरम की बैठक में मोदी ने हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरून ने 13 नवंबर को ब्रिटेन-भारत सीईओ फोरम की बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री कैमरून ने भारत में व्यापक बदलाव लाने से जुड़े प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन एवं उद्देश्य का उल्लेख किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच रिश्तों में निश्चित तौर पर आर्थिक संबंधों की खास अहमियत होती है। उन्होंने केन्द्र सरकार के अनेक कदमों जैसे कि 'मेक इन इंडिया', बुनियादी दोनों ही देशों के सीईओ (मुख्य कार्यकारी

अधिकारी) ने संक्षिप्त अवलोकन किया। यह पाया गया कि वर्तमान समय निवेशकों के लिए भारत में 'अवसर की ज्वारीय तरंग' का द्योतक है।

ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री

श्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि मैं ब्रिटिश संसद को संबोधित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं उन भारतीय लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं जिनके कारण मैं यहां आपको संबोधित कर रहा हूं।

ब्रिटिश संसद में अपने संबोधन के दौरान श्री मोदी ने कहा कि कई बातें ऐसी हैं कि किसी को भी कहना मुश्किल हो जाए कि वह ब्रिटिश हैं या भारतीय। जगुआर या स्कॉटलैंड यार्ड... उदाहरण के लिए ब्रुक बॉन्ड चाय या मेरे दिवंगत दोस्त लॉर्ड गुलाम नन की करी। इस बात पर भी बहस होती है

कि लॉर्ड्स की पिच गलत ढंग से स्विंग हो रही है या ईडन गार्डस का विकेट जल्दी टूट जाता है। **यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन के मुख्य अंश:**

लंदन में आकर मैं आह्लादित हूं। आज वैश्वीकरण के युग में लंदन आज भी हमारे समय का आदर्श बना है। इस नगर ने विश्व की विविधता को अपनाया है और यह मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों की नुमाइंदगी करता है। मैं ब्रिटेन की संसद को संबोधित कर सच्चे अर्थों में सम्मानित हूं। युनाइटेड किंगडम सिंगापुर और मॉरीशस के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत युनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश पर आधारित परियोजनाओं का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। भारतीय यूरोपीय यूनियन के शेष देशों में किए गए कुल निवेश से ज्यादा निवेश ब्रिटेन में करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह (भारतीय) खर्च बचाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वातावरण सुपरिचित एवं अभिनंदनीय लगता है।

एक सुप्रसिद्ध भारतीय व्यापारिक हस्ती टाटा ब्रिटेन की हस्ती को चलाती है और निजी क्षेत्र में आपके देश का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता बनती है। ब्रिटेन भारतीय छात्रों का पसंदीदा गंतव्य है। हम विज्ञान और तकनीक के आधुनिकतम क्षेत्रों में साथ मिल कर काम कर रहे हैं। हम खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की मानवीय समस्याओं के समाधान निकाल रहे हैं।

हमारे सुरक्षा बल परस्पर युद्धाभ्यास करते हैं ताकि वो उन मूल्यों की रक्षा हेतु शक्तिशाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके समर्थन के कारण भारत का वैश्विक संस्थाओं और साम्राज्यों में अपना उचित स्थान पाना अधिक संभव हो पाया है। और इसने दोनों देशों के साझा हितों को आगे ले जाने में मदद दी है।

हमारे जैसे संबंधों के लिए, हमारे जैसी मजबूत सहकारिता के लिए, हमारी महत्वाकांक्षाओं के मानक उच्च होने चाहिए। हम दो लोकतंत्र हैं, दो शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और दो नवपरिवर्तनशील समाज हैं। हमारे पास आपसी परिचय का लाभ और लंबी साझेदारी का अनुभव है। ब्रिटेन का पुनरुत्थान प्रभावित करने वाला है। विश्व अर्थव्यवस्था के भविष्य पर इसका प्रभाव मजबूत है।

भारत विश्व के लिए आशा और अवसर का उज्ज्वल नवीन केंद्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सार्वभौमिक निर्णय भर नहीं है। यह महज कुछ अंकों पर आधारित तर्क नहीं है। एक 1.25 बिलियन का देश जिसमें 800 मिलियन लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह आशावाद हमारे युवाओं की ऊर्जा एवं उद्यम से आता है, परिवर्तन के लिए आतुर और पाने के विश्वास से भरे हुए। यह हमारे कानूनों, नीतियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं में सुधार हेतु की गई साहसिक एवं अनवरत कार्यवाहियों का परिणाम है।

भारत विश्व के लिए आशा और अवसर का उज्ज्वल नवीन केंद्र है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सार्वभौमिक निर्णय भर नहीं है। यह महज कुछ अंकों पर आधारित तर्क नहीं है। एक 1.25 बिलियन का देश जिसमें 800 मिलियन लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं।

हम हमारे निर्माण क्षेत्र में प्राण फूंकने में लगे हैं, हमारे खेतों को अधिक फलप्रद एवं विपरीत हालात में टिकने वाला बनाने में, हमारी सेवाओं को अधिक प्रगति एवं सुघड़ बनाने में, हमारे युवाओं के वैश्विक कौशल को विकसित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने में स्टार्टअप उद्योगों में क्रांति लाने में और आगामी पीढ़ी की ऐसी अवसंरचना तैयार कर रहे हैं जिससे कि उसका मार्ग सुगम हो पाए। हमें सिर्फ हमारे विकास से ही नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में रूपांतरण के प्रयासों से ताकत मिलती है।

हमारे सपनों वाला भारत अभी भी हमसे दूर है। सबके लिए घर, विद्युत, पानी और स्वच्छता, हर नागरिक के लिए बैंक खाते और बीमा, समृद्ध और संयोजित गांव और शानदार एवं चिरस्थाई शहर। यह लक्ष्य तय तिथियों में पाये जाने हैं, न कि यह आशा की मृगतृष्णा मात्र हैं। शासन प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही है। निर्णयों में साहस और गति है। संघवाद अब केंद्र-राज्य संबंधों की नीति निर्धारक रेखा नहीं है, बल्कि टीम इण्डिया की नयी साझेदारी की परिभाषा है। नागरिकों के पास अब भरोसे की आजादी है, प्रमाण एवं प्रक्रिया का बोझ नहीं है। व्यापार के लिए खुला एवं काम करने में आसान वातावरण है। सेलफोन से जुड़े देश में डिजिटल इण्डिया, सरकार और जनता के बीच संवाद का रूपांतरण कर रहा है। यदि आप भारत आएं तो परिवर्तन की हवाओं को महसूस करेंगे।

यह विश्वभर से आने वाले निवेश में हुई वृद्धि से, हमारी अर्थव्यवस्था के बढ़ते स्थायित्व से, आशा और सामूहिकता भरे 190 मिलियन नये बैंक खातों से, प्रति वर्ष लगभग 7.5 प्रतिशत की हमारी बढ़ती विकास दर से और व्यापार करने में सुगमता के मामले में हमारी रैंकिग में तीव्र बढ़ोतरी से यह प्रकट होता है। और, सबका साथ सबका विकास का नारा देश के बारे में हमारा दृष्टिकोण है जिसमें हर नागरिक सम्बद्ध हो, भागीदार हो एवं उन्नति करे।

यह केवल आर्थिक अंतर्वेशन की पुकार नहीं है। यह हमारी बहुरूपता का उत्सव भी है, सामाजिक समरसता का मत भी है और, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति समर्पण भी है। यह हमारी संस्कृति का कालातीत चरित्र है, यह हमारे संविधान का आधार है, और यह हमारे भविष्य की नींव होगा।

भारत की प्रगति मानवता के छठे हिस्से का भविष्य है। और इसका अर्थ होगा- अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त और अपनी संपन्नता के प्रति अधिक आत्मविश्वास से भरी दुनिया। यह अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है कि हमारे आर्थिक संबंध दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। यदि हम हमारी विशिष्ट शक्तियों एवं भारत में उपलब्ध अवसरों को जोड़ें तो हम अपराजेय साझेदारियां करेंगे।

हमारा युग विश्व में हो रहे बहुत से परिवर्तनों का युग है। आने वाले भविष्य को हमें अभी पूरी तरह समझना शेष है। जैसे पिछले युगों में विश्व के वर्तमान स्वरूप की हमारी समझ अलग थी। इसलिए अनिश्चितता से भरे हमारे दौर में, हमें हमारे साझा आदर्शों के अनुरूप इस दुनिया को दिशा देने में मदद देनी चाहिए। हम ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें दूर

स्थित किसी क्षेत्र में आई अस्थिरता फौरन हमारे दर तक पहुंच जाती है। हम इसको कट्टरपंथ एवं शरणार्थियों से जुड़ी चुनौतियों के अंतर्गत देखते हैं। आतंकवाद की जद देशों की सरहदों से अंदर आकर हमारे समाज के तानेबाने और शहरों की गलियों में स्थानांतरित हो रही है। और आतंकवाद एवं अतिवाद विश्वस्तरीय बुराइयां हैं जो अपने परिवर्तित होते नामों, समूहों, क्षेत्रों और लक्ष्यों से कहीं बड़ी हैं।

हमारे समय की इस चुनौती के विरुद्ध विश्व को एक स्वर में बोलना चाहिए एवं एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। हमें देर किए बिना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र में एक विशद संधि भी करनी चाहिए। आतंकी समूहों के बीच कोई अंतर एवं देशों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो देश आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं उनको अलग-थलग करने का जज्बा एवं जो देश आतंकियों का ईमानदारी से सामना करते हैं उनके साथ खड़े होने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। और जिन देशों में अतिवाद पसरा है वहां एक सामाजिक आंदोलन की एवं धर्म को आतंकवाद से अलग करने की आवश्यकता है।

डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम जिनका 125वां जन्मदिवस मना रहे हैं। वे भारत के संविधान एवं हमारे संसदीय लोकतंत्र के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि दबाए हुए कमजोर तबकों और वंचितों के उत्थान के लिए भी खड़े हुए।

समुद्र हमारी समृद्धि के प्राणाधार बने हैं। अब हमें हमारे अंतरिक्ष एवं साइबर अंतरिक्ष की सुरक्षा भी करनी होगी। हमारे हित बहुत से क्षेत्रों में फैले हैं। एक स्थाई, संपन्न एवं समेकित दक्षिण एशिया, जो समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता हो, में हमारे साझा हित हैं। हम एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं जिसने महान अफगानी लोगों के सपनों से आकार लिया हो, न कि अतार्किक डर और दूसरों की अति महत्वाकांक्षाओं से बना हुआ अफगानिस्तान। शांतिपूर्ण एवं स्थाई हिंद महासागर क्षेत्र विश्व वाणिज्य एवं समृद्धि के लिए अति आवश्यक है। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के भविष्य का प्रभाव हम सभी पर होगा। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र से हम दोनों के हित जुड़े हैं।

हमें हमारे ग्रह के दीर्घकालिक भविष्य हेतु अल्प कार्बन उत्सर्जन युग के लिए सहयोग करना चाहिए। यह एक वैश्विक जिम्मेदारी है जिसको हमें इसी महीने के उत्तरार्द्ध में देखना है। सम्मिलित प्रयासों से विश्व में एक शानदार संतुलन कायम है। अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उत्तरदायित्वों का समावेश। जिनके पास साधन और जानकारी है उन्हें स्वच्छ ऊर्जा एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए मानवता की सार्वभौमिक आकांक्षाओं की प्राप्ति में अवश्य मदद करनी चाहिए। और जब हम सख्ती की बात करते हैं तब हमें जीवाश्म ईंधन पर अंकुश की बात ही नहीं बल्कि अपनी जीवनशैली में भी निग्रह करना चाहिए। हमें अपनी भूमिका निबाहनी चाहिए। भारत के लिए 2022 तक 175 गीगावॉट की अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा एवं 2030 तक उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत की कमी एक विशद रणनीति के दो कदम हैं। मैंने कॉप-21 (कांफ्रेस ऑफ पार्टीज) बैठक के दौरान सौर ऊर्जा को अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनाने और कटे हुए गांवों तक को जोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने का प्रस्ताव किया है।

हम दोनों महान राष्ट्रों के लिए यह एक बड़ा क्षण है। इसलिए हमें अवसर भुनाने चाहिए, सहयोग के मार्ग की बाधाएं हटानी चाहिए, अपने रिश्तों में पूरा विश्वास भरना चाहिए और एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा करने से हम हमारी रणनीतिक साझेदारी को रूपांतरित कर देंगे और यह संबंध बड़ी वैश्विक साझेदारियों में गिने जाएंगे। अक्सर, ब्रिटेन के लब्धप्रतिष्ठित समर्थकों के मुताबिक सामाजिक समस्याओं के समाधान में जनभावना की इस विशाल लहर का सदुपयोग होना चाहिए।

डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम जिनका 125वां जन्मदिवस मना रहे हैं। वे भारत के संविधान एवं हमारे संसदीय लोकतंत्र के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि दबाए हुए कमजोर तबकों और वंचितों के उत्थान के लिए भी खड़े हुए। और मानवता की सेवा के एक उच्च कार्य के लिए, न्याययुक्त भविष्य के लिए, समानता एवं सभी मनुष्यों के लिए प्रतिष्ठा और समान अवसर मुहैया कराने के लिए, साथ ही लोगों के बीच शांति के लिए उन्होंने हमें तैयार किया।

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के मेहमान बने मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने ब्रिटेन दौरे के दूसरे दिन 13 नवंबर को महारानी एलिजाबेथ से मिलने उनके महल बकिंघम पैलेस पहुंचे। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने बकिंघम पैलेस पहुंचे। महारानी ने खुद महल के मुख्य द्वार पर श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय

प्रधानमंत्री श्री मोदी को शाही संग्रहालय भी ले गई और श्री मोदी की मेहमाननवाजी में दोपहर का भोज भी दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी को कुछ खास फोटोग्राफ उपहार में भेंट किए, जिन्हें जनवरी-फरवरी 1961 को

भारत में उनकी प्रथम यात्रा के समय 54 वर्ष पूर्व खींचा गया था। महारानी उस वक्त नई दिल्ली में गणतन्त्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि थी। अपनी इस यात्रा के दौरान, महारानी ने वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, कोलकाता, मुम्बई, बैंगलूरु और चेन्नई सहित कुछ अन्य शहरों की भी यात्रा की थी।

31 जनवरी, 1961 को खींचा गया पहला चित्र महात्मा गांधी की 13वीं पुण्यतिथि के एक दिन बाद, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में उनकी यात्रा को दर्शाता है।

दूसरा चित्र 19 फरवरी, 1961 को चेन्नई में खींचा गया था और यह उस वक्त के मद्रास राज्य के द्वारा उनके सम्मान में स्वागत समारोह को दर्शाता है, उन्हें योर्क के ड्यूक, एच.आर.एच प्रिंस एंड्रयू के प्रथम जन्मदिवस के अवसर पर एक केक प्रस्तुत किया गया था।

तीसरा चित्र 25 फरवरी, 1961 को खींचा गया था जिसमें महारानी को वाराणसी के बलुआ घाट में एक जुलूस में एक हाथी की सवारी करते दिखाया गया है, वाराणसी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।

24 फरवरी, 1961 को खींचा गया एक और चित्र महारानी की ट्राम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र की यात्रा को दर्शाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने महारानी को पश्चिम बंगाल के मकई-बाड़ी चाय बागान से कुछ पुरस्कार प्राप्त चाय, जम्मू और कश्मीर से उत्कृष्ट ऑर्गेनिक शहद और वाराणसी की विशेषता के तौर तनचोई ओढ़नी भेंट दीं। ■

प्रधानमंत्री ने पेरिस में हुए आतंकी हमलों की निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में हुए आतंकी हमलों की निंदा की। उन्होंने लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुये हमलों की निंदा की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, 'कल जो पेरिस में हुआ । मानवता पर हमला हुआ। और दुनिया को मानना पड़ेगा यह हमला पेरिस पर नहीं है, यह हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, यह हमला फ्रांस पर नहीं है, यह हमला मानवता पर है। मानवतावादी विचारों पर है और इसलिए मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों को इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी। और मानवतावादी शक्तियों को आगे आकर के मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी।

मैं चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र जो अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। वह अब समय न बिताये। जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की परिभाषा तय करे। यह प्रस्ताव उनके सामने पड़ा हुआ है ताकि पता चले कि कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद की मदद करता है, किसकी आतंकवाद के प्रति कृपा है। कौन है जो आतंकवाद का शिकार है, कौन है जो आतंकवाद का विरोध करता है, कौन है जो मानवतावादी विचारों के लिए खुद को खपाने के लिए तैयार है। समय की मांग है कि अब इन घटनाओं से विश्व की मानवतावादी शक्तियां समय बीतने से पहले एक साथ आएं और एक साथ ऐसी शक्तियों को अलग-थलग करें, उनको परास्त करने की रणनीति बनाएं।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस में हुए हमले का समाचार बहुत दुखदायी और भयानक है। मृतकों के परिवारों के प्रति मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम फ्रांस की जनता के साथ एकजुट हैं। ■

जी-20 शिखर सम्मेलन

आतंकवाद से लड़ना बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए : नरेंद्र मोदी

जी-20 की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए तुरंत और एकीकृत वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। तुर्की की अंताल्या शहर में 15 नवंबर को संपन्न हुई जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को आतंकवाद के खतरे के बारे में आगाह किया है। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का चरित्र बदल रहा है लेकिन आज भी कुछ देश आतंकवाद के पुराने स्ट्रक्चर को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री मोदी ने जी-20 से इतर ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ अपनी बैठक में पेरिस में आतंकवाद की कायरतापूर्ण हरकतों की निंदा भी की। श्री मोदी ने कहा कि पूरे मानव समाज को आतंकवाद के खिलाफ मिलकर खड़े होना चाहिए। उन्हें आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। ब्रिक्स देशों की भी यही प्राथमिकता होनी चाहिए।

मिस्र के सिनाई इलाके में एक रुसी यात्री विमान गिरने की घटना के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि हम सिनाई की दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर रुस के साथ गहरी सहानुभूति जताते हैं। अंकारा और बेरुत की घटनाएं भी हमें आतंकवाद के बढ़ते प्रसार और प्रभाव के प्रति सतर्क करती हैं। प्रधानमंत्री ने जी-20 देशों से आतंकवादियों का वित्त पोषण रोकने, आपूर्ति और संचार माध्यमों को समाप्त करने की व्यापक वैश्विक रणनीति समेत सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में कड़ी वैश्विक कार्रवाई करने का आह्वान किया।

श्री मोदी ने कहा कि ये घटनाएं उन बुरी ताकतों की प्रतीक हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं जो किसी खास लक्ष्य, क्षेत्रों या समूहों की पहचान से परे है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक बड़ी वैश्विक चुनौती है। यह न केवल लोगों की जान ले रही है बल्कि इसकी बड़ी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ रही है और साथ ही इसने हमारी जीवन शैली को खतरा पैदा कर दिया है। इससे

निपटने के लिए व्यापक वैश्विक कार्रवाई की जरूरत है। इसके खिलाफ लड़ाई जी-20 की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

एकजुट होकर करेंगे आतंकवाद का खात्मा: जी-20

राजनीतिक विषयों पर अपने पहले संदेश में दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देशों के समूह जी-20 के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने पेरिस में हुए बर्बर आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने और आतंक के वित्तीय स्रोतों को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया। अंताल्या शिखर सम्मेलन में पहली बार जी-20 देशों के नेताओं ने आर्थिक व कारोबारी विषयों से इतर एक बयान जारी किया और पेरिस हमलों की भर्त्सना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प व्यक्त किया। तुर्की के राष्ट्रपति श्री रिसेप तायिक एर्दोगन की ओर से दिए गए रात्रि भोज के दौरान 'वैश्विक चुनौतियां: आतंकवाद और पलायन' विषय पर बयान का आधार तय हुआ। दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त बयान में इस बात को रेखांकित किया गया है कि नेताओं ने इसकी फिर से पुष्टि की कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूहों से नहीं जोड़ा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन सहित जी-20 के सभी नेताओं ने पेरिस पर हुए बर्बर हमले की निंदा की और इस बात को दोहराया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए वे एक रहेंगे। विदेशी आतंकी लड़ाकों के बढ़ते प्रवाह पर चिंता प्रकट करते हुए जी-20 देशों के नेताओं ने मांग की कि इसे रोकने के लिए सीमा नियंत्रण और हवाई सुरक्षा को कड़ा किया जाए। इन नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादियों के वित्त पोषण के स्रोतों को खत्म करने के लिए और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए वे सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी आपसी सहयोग को बनाए रखेंगे।

जी-20 नेताओं की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आतंकियों के वित्त पोषण के माध्यमों से निपटने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, खास तौर पर आतंकवादियों की सम्पत्तियों को जब्त करने और आतंकवादियों के वित्तपोषण को आपराधिक कार्य घोषित करने के लिए वे सूचनाओं के आदान प्रदान करने में आपसी सहयोग जारी रखेंगे। इन नेताओं ने आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ सख्त लक्षित वित्तीय प्रतिबंध व्यवस्था बनाने की अपील की। इसमें सभी क्षेत्रों में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) को सुगम तरीके से लागू करना शामिल है। बयान में कहा गया कि हम एफएटीएफ की प्रासंगिक सिफारिशों को लागू करना जारी रखेंगे। हम एफएटीएफ को सुझाव देते हैं कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए उसके लक्षित वित्तीय पोषण के स्रोतों को चिन्हित करके वित्तीय प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करे।'

अंताल्या घोषणा में वैश्विक पलायन की समस्या का भी उल्लेख किया गया और सभी देशों से इस समस्या का समाधान करने की अपील की गई। जी-20 देशों के नेताओं ने फैसला किया कि वे मिलकर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और मानवाधिकार कानूनों, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक आतंकवाद को रोकने और उसे समाप्त करने की दिशा में मिलकर काम करे। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

जी-20 देशों का आर्थिक विकास में दो प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य

जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2018 तक दो प्रतिशत अतिरिक्त इजाफा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद साझा बयान में कहा गया कि 2018 तक सभी सदस्य देशों ने जीडीपी में दो प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्तीय बाजार की सूचना का आदान प्रदान करके नीतिगत फैसले, बाजारों की संवेदनशीलता और अमेरिकी ब्याज दर में वृद्धि पर निर्भर रहना होगा।

बयान में कहा गया कि पिछले साल हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में भी जीडीपी में दो प्रतिशत अतिरिक्त इजाफा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस बार दोबारा से इसके प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। बयान में कहा गया कि सदस्य देशों की मुख्य प्राथमिकता समय पर तथा प्रभावकारी तरीके से विकास नीति का कार्यान्वयन होगा।

प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद निरोधक रणनीति व अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संधियों के दायरे में सहयोग करने की बात भी कही गई है।

बयान के मुताबिक, 'हम सख्त से सख्त शब्दों में पेरिस में 13 नवंबर और अंकारा में 10 अक्तूबर को हुए बर्बर आतंकी हमलों की निंदा करते हैं। यह पूरी मानवता के लिए अस्वीकार्य है।' इसमें कहा गया, 'हम आतंकी हमलों के शिकार लोगों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। हम आतंकवाद के सभी स्वरूपों और जहां भी यह घटता है, उसके विरुद्ध एकजुटता और उससे लड़ने के संकल्प को दोहराते हैं।' समूह के नेताओं ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं।

2022 तक अक्षय उर्जा उत्पादन बढ़ाकर 175 गीगावाट करने का संकल्प: प्रधानमंत्री

साल 2022 तक भारत की अक्षय उर्जा उत्पादन क्षमता को चौगुना कर 175 गीगावाट करने तथा जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी घटाने का संकल्प जताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के प्रमुख देशों से ऐसी सहायक प्रणाली बनाने को कहा जो कि उन देशों पर केंद्रित हों जहां वृद्धि की अधिकतम संभावनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने उक्त देशों से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण मुख्य प्राथमिकता के रूप में करते रहने को कहा।

श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में 'विकास व जलवायु परिवर्तन' विषय पर चर्चा के दौरान सात सूत्री सुझाव पेश किए जिनमें 'कार्बन क्रेडिट' से 'ग्रीन क्रेडिट' की ओर जाना तथा 2030 तक शहरों में आवागमन के साधनों सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का हिस्सा बढ़ा कर 30 प्रतिशत तक पहुंचाने का सुझाव शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम विचार करें कि कैसे जी-20 मदद की ऐसी प्रणाली बना सकता है जो कि उन देशों पर केंद्रित हों जहां वृद्धि की अधिकतम संभावनाएं हैं, जो उनकी विशिष्ट बाधाओं को दूर कर सके तथा देशों की विशेष रणनीतियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाए। श्री मोदी ने कहा कि अमेरिका व चीन सहित दुनिया की 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के इस संगठन को बुनियादी ढांचा पर ध्यान देते रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा व पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे से विकास तथा जलवायु परिवर्तन, दोनों ही चुनौतियों से निपटा जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा वित्त पोषण में मौजूदा अंतर समाप्त करना हमारी मुख्य प्राथमिकता रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आर्थिक व राजकाज के क्षेत्र में साहसिक सुधारों से हम करीब 7.5 प्रतिशत की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सके हैं और निकट भविष्य में इसके और तेज होने की संभावना है। ■

हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नैतिक आधार पर इस्तीफा दें : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लांडरिंग के मामले में तीन राज्यों में छापेमारी की है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है श्री बीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार के राज खुलते जा रहे हैं। सीबीआइ और ईडी की कारवाई से श्री वीरभद्र सिंह और उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार और कालाधन सफेद करने के आरोप सच साबित हुए हैं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले पर मौन है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक श्री बीरभद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व श्री बीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार और कालेधन पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहा है। भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस नेतृत्व का यह मौन कई सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस नेतृत्व इसलिए मौन है कि उसे हिमाचल प्रदेश में हुए घोटाले से हिस्सा मिला? हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस नेतृत्व को श्री बीरभद्र सिंह के घोटाले से कितना हिस्सा मिला? जनता जानना चाहती है कि सोनियाजी और राहुलजी आपकी वह कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप भ्रष्टाचार के आरोपी श्री बीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने और कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं? दुष्प्रचार में माहिर राहुल गांधी की भ्रष्टाचार पर चुप्पी शर्मनाक है। इससे कांग्रेस के दोहरे मापदंड भी उजागर हो गए हैं। एक बार फिर साबित हो गया है कि टूजी, सीडब्ल्यूजी और आदर्श जैसे बड़े-बड़े घोटाले अंजाम देने वाली कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपियों को संरक्षण देती है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मांग की कि श्री वीरभद्र सिंह में जरा सी भी नैतिकता हो तो उन्हें अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ■

यह रास्ता कांग्रेस को कहां ले जाएगा

✍ बलबीर पुंज

क्या कांग्रेस की बहुत सारी आस्थाएं सिर्फ तभी तक हैं, जब तक वह सत्ता में है? कभी वह भी समय था, जब सत्ता से बाहर होने के डर से कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए देश में आपातकाल लागू किया था। अब तो वह सचमुच सत्ता से बाहर है, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया भी उसी अनुपात में उग्र है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने पिछले दिनों जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उनमें यह उग्रता तो देखी ही जा सकती है, साथ ही इससे उनकी आस्था पर भी शक होता है। भारी बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और इसके लिए उन्हें कुछ भी कहने से गुरेज नहीं है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने विगत 12 नवंबर को इस्लामाबाद स्थित जिन्ना संस्थान में आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। उस अवसर पर उन्होंने कहा, 'लोकतांत्रिक पाकिस्तान में यदि किसी गैर सैन्य शासक ने भारत के साथ शांति कायम करनी चाही, तो वह नवाज शरीफ हैं।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'यदि दोनों प्रधानमंत्री की भाव-भंगिमा को देखें, तो आपके प्रधानमंत्री ने दूरदर्शी और साहसिक कदम उठाया था। उस दौरे के बाद हमने जो कहा और किया उसके कारण असहज परिस्थितियां बनीं।' वहीं कांग्रेस के एक अन्य बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में कहा- यदि भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत बहाल करनी है, तो प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटाना होगा। आगे उन्होंने कहा, 'हमें सत्ता में वापस लाएं और उन्हें हटाएं।'

इन दोनों नेताओं ने जो कहा, उसका सार यह था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो शांति के दूत हैं, पर जब तक मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, दोनों देशों के बीच शांति नहीं हो सकती। यानी पाकिस्तान तो अमन चाहता है, किंतु भारत ही झगड़ रहा है। इन दोनों नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर क्या पाकिस्तान के हाथों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का हथियार नहीं थमा दिया है?

अभी हाल तक केंद्र में लगातार दस वर्षों कांग्रेस की सरकार रही। अय्यर और खुर्शीद के लिए यदि देश सर्वोपरि होता, तो वे पाकिस्तान में यह सवाल उठाते कि आखिर मुंबई के 26ध्11 के हमले के असली गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद और लखवी को पाकिस्तानी हुक्मरान गले से क्यों लगाए घूमते हैं? कैसे पाकिस्तान में हाफिज सईद खुलेआम भारत को तबाह करने की धमकी देता है? सईद और लखवी पर इन दोनों नेताओं की चुप्पी, नवाज शरीफ की प्रशंसा व प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विष-वमन के क्या अर्थ हैं?

मनमोहन सिंह दस साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म चकवाल के उस गह गांव में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। देश के रक्तरंजित विभाजन के बाद एक शरणार्थी के रूप में उन्हें यहां आना पड़ा था, किंतु गह से उनका भावनात्मक लगाव टूटा नहीं। एक प्रधानमंत्री के रूप में वह वहां जा सकते थे, किंतु वह जा नहीं पाए, क्योंकि उन दस वर्षों में वह और उनकी पार्टी पाकिस्तान के साथ शांति व मैत्री कायम नहीं कर पाए? यदि कांग्रेस के पास दोनों देशों के बीच अमन कायम करने के लिए जादुई चिराग था, तो मुंबई पर आतंकी हमला ही क्यों हुआ था? उस आतंकी हमले में 166 निरपराध मारे गए थे।

पेरिस पर हाल का आतंकी हमला तो उसी बर्बरता की पुनरावृत्ति है। दोनों देशों के बीच मैत्री कायम हो, इसके लिए तमाम समझौते करते रहने के बावजूद मनमोहन सिंह विफल रहे। पाकिस्तान को तुष्ट करने के लिए ही मनमोहन सिंह सन 2009 में शर्म-अल-शेख में भारत-पाक द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में बलूचिस्तान में भारत द्वारा अशांति उत्पन्न करने की बात को स्वीकृति दे आए थे। पहली बार भारत के पारंपरिक रुख में मनमोहन सिंह ने गुलाटी मारकर देश को शर्मसार किया था। इसके बावजूद वह भारत-पाक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला सके।

भारत के प्रति शत्रुता पाकिस्तान के डीएनए में ही समाहित है। पूत के पांव

शेष पृष्ठ 30 पर

संविधान दिवस की सार्थकता

✍ कृपाशंकर चौबे

केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद संविधान के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करना है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रत्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 जनवरी, 1950 को इस पर संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही यह प्रभावी हो गया। 26 जनवरी को ही देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को स्वीकार किया गया। संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 हिस्से, 12 अनूसूचियां, पांच परिशिष्ट और 98 संशोधन हैं। इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 51 ए में वर्णित पहले मौलिक कर्तव्य के अनुसार, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, लेकिन पालन और आदर तो तब किया जा सकेगा जब हर नागरिक संविधान को जाने-समझे और हृदयंगम करे? नागरिकों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि उन्हें पूरे संविधान की जानकारी भले न हो, किंतु संविधान की बुनियादी बातों का और कम से कम मूल कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी उन्हें होनी ही चाहिए। वास्तविकता यह है कि देश की एक बड़ी आबादी ने संविधान शब्द को ही नहीं सुना है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? अब जब हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हो रही है तो क्या यह उम्मीद की जाए कि संविधान की मूलभूत बातों का ज्ञान जन-जन तक पहुंचाने का ठोस उपाय किया जाएगा। यह एक तथ्य है कि अधिकतर नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों और अधिकारों तक की जानकारी नहीं है?

पहले मौलिक कर्तव्य के अनुसार, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, लेकिन पालन और आदर तो तब किया जा सकेगा जब हर नागरिक संविधान को जाने-समझे और हृदयंगम करे? नागरिकों से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि उन्हें पूरे संविधान की जानकारी भले न हो, किंतु संविधान की बुनियादी बातों का और कम से कम मूल कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जानकारी उन्हें होनी ही चाहिए।

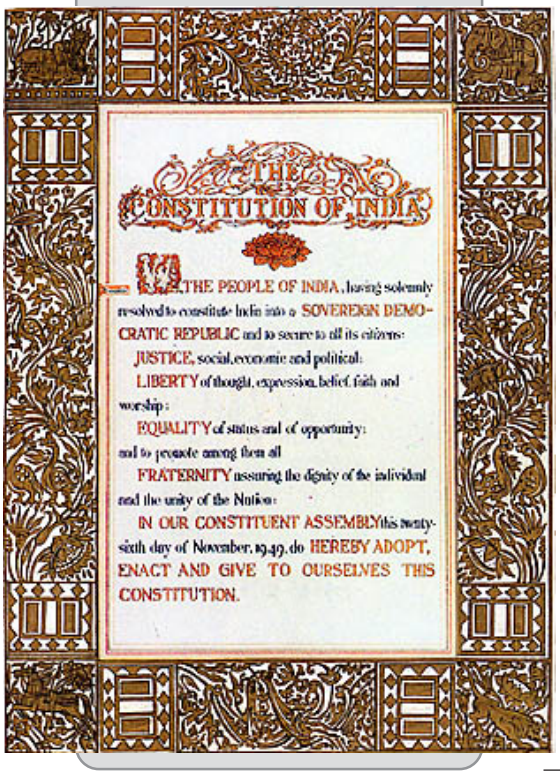

संविधान को लागू हुए पैंसठ साल हो गए, फिर भी आवश्यक चेतना का प्रसार नहीं हो सका है। नागरिकों में संविधान की मूलभूत बातों को जानने की जरूरत का अहसास जगाने के लिए आवश्यक था कि उसके

प्रति रुचि जागृत की जाती, लेकिन ऐसी कोशिश ईमानदारी से कभी की ही नहीं गई। आज अनेक नागरिक समस्याओं का मूल कारण यही है कि अधिकांश नागरिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, अपने मूल कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। संविधान के अनुसार नागरिकों का दूसरा कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखना और उनका पालन करना बताया गया है। तीसरा कर्तव्य है–भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसकी मर्यादा बनाए रखना। चौथा– देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा।

पांचवां– भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा– सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सातवां– प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा और उसका संवर्धन तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव। आठवां– वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। नौवां–सार्वजनिक संपति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। दसवां– व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ग्यारहवां और अंतिम कर्तव्य है– माता–पिता छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाली संतान को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में प्रमुख हैं– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

आम भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति तो थोड़े सजग दिखते भी हैं, किंतु कर्तव्यों के प्रति प्रायः उनमें सजगता नहीं दिखती। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रति भी अधिसंख्य नागरिकों में वांछित सजगता नहीं नजर आती। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

आम भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति तो थोड़े सजग दिखते भी हैं, किंतु कर्तव्यों के प्रति प्रायः उनमें सजगता नहीं दिखती। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रति भी अधिसंख्य नागरिकों में वांछित सजगता नहीं नजर आती। इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन–साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों, बालकों को गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

संविधान दिवस की सार्थकता के लिए उसकी मूलभूत बातें नागरिकों को बताने के लिए गांव–कस्बा स्तर तक अभियान चलाना होगा। इस तरह का अभियान कुछ लोग चला रहे हैं। इनमें गिरीश पांडेय प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों में पांडेय अपनी सभाओं में संविधान की मूलभूत बातों को सरल ढंग से नागरिकों को समझाते हैं और जागो गणराज्य जागो नामक पुस्तिका वितरित करते हैं।

संविधान की मूलभूत बातों का जितना अधिक प्रचार होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। संविधान की मूलभूत बातों की जानकारी नागरिकों में नवजागरण लाने का निमित्त बन सकती है। ■

(दै. जागरण से साभार)

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मेलन 2015

राजस्थान देश में निवेश के लिए पसंदीदा राज्य : अरुण जेटली

पिछले दिनों जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मेलन, 2015 संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 19-20 नवंबर को आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि राजस्थान देश में निवेश के मामले में सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। रिसर्जेंट राजस्थान समिट 2015 के उद्घाटन के मौके पर श्री

जेटली ने कहा कि केन्द्र की एफआईडी पॉलिसी से सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को ही होगा। सम्मेलन में राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे समेत केंद्रीय सरकार के कई मंत्री और कई दिग्गज उद्योगपति मौजूद थे। श्री जेटली ने राजस्थान सरकार की व्यापार करने में सहूलियत की नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश से राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा राजस्थान के विकास के दो प्रमुख अंग हैं। रिसर्जेंट राजस्थान अब इतिहास और पर्यटन के अलावा निवेश के क्षेत्र के लिए भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की पहचान देश दुनिया में बनेगी। श्रम सुधारों के मामले में राजस्थान ने अन्य राज्यों पर दो साल आगे है। उन्होंने मुख्यमंत्री राजे के निवेश सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि पहले राजस्थान बीमारू राज्य हुआ करता था लेकिन अब राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में सुधार हो रहा है।

श्री जेटली ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन पर भी वार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्व में बिजली कंपनियों के कर्ज का जिक्र करते हुए कहा कि इस कर्जे से मौजूदा अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। लेकिन वसुंधरा राजे के प्रयासों से अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने कहा कि हम भारत के स्टार्टअप इनोवेशन हब के रूप में उभर रहे हैं। हमने पारदर्शिता लाने के लिए खानों का आवंटन ई-ऑक्शन के जरिए करने का फैसला किया है। हम राज्य के लघु और मझोले उद्योगों को फिर से पटरी पर लाएंगे। फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चैन, फार्म मशीनरी और पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान के विकास के लिए हमने वैश्विक साझेदारियां की है।

केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री श्री वैंकया नायडू ने कहा कि राजस्थान कई आवासीय योजनाओं को देश में पहली बार लागू करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ करार करने की पहल सबसे पहले की, जिससे फायदा भी मिला। श्री नायडू ने केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद का वायदा किया। श्री नायडू ने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के सहयोग के सिद्धांतों के तहत केन्द्र सरकार राज्य सरकार की मदद करेगी। इसके तहत राज्यों को आगे बढने के अवसर मिलेंगे। श्री नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत चिन्हित 100 शहरों में से चार राजस्थान से हैं।

इस अवसर पर रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय ढांचागत विकास के लिये जल्दी ही राजस्थान के साथ एक संयुक्त उद्यम लगायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य के 24 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जायेगा। रिसर्जेंट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रभु ने कहा कि राज्य में रेलवे के ढांचागत विकास के लिये रेलवे और राजस्थान सरकार एक संयुक्त उद्यम लगायेगी। इसके तहत केन्द्र और राज्य सरकार एक संयुक्त

4 लाख करोड़ रुपए का आया निवेश

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। समिट के उद्घाटन से पहले 3.30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। समिट के दौरान 70 हजार करोड़ रुपए के नए एमओयू पर सहमति बनी। सबसे अधिक निवेश सोलर पॉवर में आया। इस क्षेत्र में 1.90 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। दूसरे पायदान पर खनन सेक्टर रहा। इसमें 77,657 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर मुहर लगी। तीसरे नंबर पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रहा। इसमें करीब 55 हजार करोड़ रुपए का नया निवेश राजस्थान में आया।

कम्पनी बनायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिये केन्द्र सरकार हर संभव मदद के लिये प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार ने राजस्थान के विकास के लिये हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि सरकार पांच हजार पांच सौ करोड रूपए के निवेश से राजस्थान के गढेपान में चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड के ब्राउन फील्ड में यूरिया उत्पादन के लिये फर्टिलाइजर इकाई स्थापित करेगी।

श्री कुमार ने घोषणा की कि सरकार चित्तौड़गढ में 100 करोड़ रुपये की लागत से सिंगल सुपर फास्फेट संयत्र की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यूरिया की मांग को पूरी करने के लिये सरकार इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करायेगी। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र ने प्रदेश में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर इन्क्यूबेशन सेंटर खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राज्य के सभी जिलों में इस तरह के सेंटर खोलने की योजना है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा स्वावलम्बी बने।

समिट के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजस्थान में पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की शाखा शुरू की जाएगी और फिर जल्द ही उसे पूर्ण संस्थान का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए टैक्सटाइल, वस्त्र और फर्नीचर डिजाइन पर पाठयक्रम शुरु किए जा सकते हैं। ■

पृष्ठ 26 का शेष...

तो पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। अपने जन्म के कुछ ही दिनों बाद, 20 अक्तूबर, 1947 को पाकिस्तानी मेजर जनरल अकबर खान ने कबाइली सेनाओं की आड़ में जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला बोला था। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला युद्ध 1965 में हुआ।

तब देश की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में थी। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और उस युद्ध में भारत की जीत का श्रेय इंदिरा गांधी को मिला।

इन सब शर्मनाक पराजयों के बाद से पाकिस्तान ने भारत को रक्तरंजित करने के लिए आतंकवाद के रास्ते परोक्ष युद्ध का मोर्चा खोल रखा है। उपरोक्त तीनों युद्धों में देश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हाथ में था। अटलजी के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ मैत्री कायम करने के गंभीर प्रयास हुए थे, किंतु कारगिल में युद्ध छेड़कर पाकिस्तान ने एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपने का काम किया।

भारत और पाकिस्तान के संबंध में इस बात से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि सीमा के इस पार या उस पार प्रधानमंत्री कौन है। वास्तव में, यह संघर्ष दो विचारधाराओं का है। जहां भारत इस देश की बहुलतावादी सनातन संस्कृति में विश्वास रखता है, वहीं पाकिस्तान का जन्म जिन कारणों से हुआ और उसका दर्शन उसे भारत के विरोध में खड़ा करता है। जो लोग पाकिस्तान के साथ शांति और मैत्री कायम करने को उतावले हैं, उन्हें पहले इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए कि पाकिस्तान में दिन-प्रतिदिन मजहब के आधार पर मुसलमानों में ही मार-काट क्यों मची है? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आखिर मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक, अजरबैजान, अल्जीरिया, बहरीन, लेबनान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि मुस्लिम बहुल देश मजहबी हिंसा में क्यों झुलस रहे हैं?

क्या यह महज संयोग है कि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के आने के बाद कांग्रेस के नेता वही बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है? कांग्रेसी नेताओं को यह भी गलतफहमी है कि ऐसा करके वे देश के मुसलमानों की भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस देश के मुसलमान अन्य मतावलंबियों की तरह ही देशभक्त हैं। वास्तव में कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देकर न केवल भारत के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि इस देश के अल्पसंख्यकों का भी अपमान कर रहे हैं। ■

(हिंदुस्तान से साभार)